न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल और न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया, के समक्ष

भारत संघ और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

आशीष (नाबालिग) और एनोटियर—प्रतिवादी

2012 का एलपीए नंबर 1615

मई 01, 2013

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) - एस एस 2 (पी), 2 (एन) (iii) (iv), 4, 5, 6, 8, I2 (l) (c), 35 - रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देश दिया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के वंचित समूह के लिए 25% आरक्षित श्रेणी के तहत कक्षा 6 में भर्ती हो - क्या आरक्षण प्रदान करने के लिए आरटीई अधिनियम के प्रावधान जमाखोरी स्कूलों पर लागू होंगे? क्या धारा 12(1) कक्षा VI से शुरू होने वाले जमाखोरी स्कूलों पर लागू होगी - यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सैनिक स्कूल कक्षा 1 हट से कक्षा VI से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आरटीई अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, इस तथ्य के बावजूद कि वे धारा 2 (एन) (iii) के साथ पठित धारा 2 (पी) के तहत एक निर्दिष्ट स्कूल थे - बोर्डिंग/सैनिक स्कूल इस प्रकार आरटीई अधिनियम के हिट से बाहर ले जाए गए - धारित - की अनिवार्य आवश्यकता 25% आरक्षण जमाखोरी स्कूलों और अनाथालयों के लिए नहीं होगा। अपील की अनुमति

माना जाता है कि धारा 5, 6, 8 और नियम 6 और सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान केस (सुप्रा) के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांतों को पढ़ने से पता चलता है कि आरक्षण का उद्देश्य पड़ोस के क्षेत्र से संबंधित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और इसे पूरे राज्य में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। और 25% आरक्षण की अनिवार्य आवश्यकता

बोर्डिंग स्कूलों और अनाथालयों तक विस्तारित नहीं होगी जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।

(पैरा 13)

अपील की अनुमति

अपीलकर्ताओं *के लिए वकील अंजलि कुक्कर।*

बलराज गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 1-कैविएटर के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति संधावलिया

(1) "वर्तमान इंट्रा कोर्ट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के 18.04.2012 के फैसले और बाद के आदेश दिनांक 31.08.2012 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत वर्तमान अपीलकर्ता के समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया गया है। आक्षेपित निर्णय के तहत, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी-आशीष (नाबालिग) को सत्र 2012-13 के लिए कक्षा 6 में भर्ती कराया जाए, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह से संबंधित 25% आरक्षित श्रेणी के स्कैट्स के तहत है। 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5350, अंकित (नाबालिग) बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें 02.11.2011 को फैसला किया गया था कि उक्त निर्णय वर्तमान आसानी से पूरी तरह से लागू था। अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए भारत संघ द्वारा जारी दिनांक 16.02.2012 के एक पत्र को भी रद्द कर दिया गया था।

(2) 'आसानी के तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता ने सिविल रिट याचिका दायर की जिसमें 07.02.2012 के परिणाम और वर्ष 2012-13 के लिए प्रवेश नोटिस को रद्द करने की मांग

की गई थी, इस आधार पर कि 25% मुहरें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के वंचित समूह से संबंधित छात्रों के लिए आरक्षित नहीं थीं, भले ही बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संक्षेप में 'आरटीई अधिनियम') 01.04.2010 से प्रभावी हुआ था। तदनुसार, निर्देश प्रार्थना की गई थी कि सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, करनाल में रिट याचिका दायर करने वाले को छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाना चाहिए। रिट याचिका में यह दलील दी गई थी कि रिट याचिकाकर्ता समाज के एक वंचित समूह से संबंधित है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिट याचिकाकर्ता की मां के पक्ष में 09.02.2011 को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। मां की आय को ृ800 प्रति माह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया। प्रतिवादी/अपीलकर्ता नंबर 2- स्कूल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई स्कैट आरक्षित किए बिना सत्र 2012-13 के लिए प्रवेश नोटिस जारी किया था और रिट याचिकाकर्ता ने 25% एससीएटी के तहत 6 वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और परिणाम 07.02.2012 को घोषित किया गया था। तदनुसार, आरटीई अधिनियम और अंकित के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। (सुप्रा)।

(3) अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लिखित बयान में, यह कहा गया था कि रिट याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था जिसमें 15% आरक्षण था और जब रिट याचिकाकर्ता मेरिट सूची में सफल नहीं हुआ, तो उसने स्कूल में प्रवेश पाने के लिए वर्तमान सहारा अपनाया। सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना वर्ष 1961 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए लड़कों को अकादमिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। सैनिक स्कूलों ने कक्षा 6 और 9 में लड़कों को दाखिला दिया और 67% स्कैट्स उस राज्य के लड़कों के लिए आरक्षित थे जिसमें स्कूल स्थित है और शेष स्कैट्स राज्य के बाहर के लोगों के लिए उपलब्ध थे। इसके अलावा, रक्षा कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों के बेटों के लिए 25% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित लड़कों के प्रवेश के लिए क्रमशः 15% और 7-1/2% स्कैट्स आरक्षित थे। सैनिक स्कूल कक्षा 1 से शुरू नहीं

हुआ और कक्षा VI में शुरू हुआ और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के प्रावधान 16.02.2012 के पत्र के अनुसार सैनिक स्कूलों पर लागू नहीं थे, जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5350 में इस न्यायालय द्वारा पारित फैसले के बारे में अंकित (नाबालिग) बनाम भारत संघ और अन्य 02.11.2011 को फैसला किया गया था, उस समय यह दलील दी गई थी कि आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के प्रावधानों के तहत छूट के लिए आसानी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से विचार कर रही थी। तथापि, इस पर विचार नहीं किया गया और शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए स्कूलों में 25% स्कैट्स भारत सरकार द्वारा आरक्षित नहीं किए गए थे। 'रिट याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के साथ गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड को संलग्न नहीं किया था और अनुसूचित जाति श्रेणी में 15% स्कैट्स के खिलाफ आवेदन किया था, लेकिन आरक्षित सीटों के तहत 07.02.2012 को प्रकाशित मेरिट सूची में नहीं आया था।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंकित के मामले (सुप्रा) *में निर्णय के आधार पर अपना निर्णय दिया,* जिसमें यह माना गया था कि यहां तक कि जहां एक स्कूल कक्षा 6 वीं से शुरू होता है, यह आवश्यक रूप से पालन करेगा कि अभिव्यक्ति 'कक्षा एफ को स्कूल द्वारा दी गई शिक्षा की पहली कक्षा के रूप में पढ़ा जाना था और सैनिक स्कूल एक निर्दिष्ट स्कूल होने के नाते आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य था। इसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा राजस्थान के *अनएडेड प्राइवेट स्कूलों के लिए सोसायटी* बनाम *भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए समीक्षा/रिकॉल आवेदन दायर किया गया था और एक अन्य*[1] जहां, निर्णय के पैरा नंबर 13 पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि भारत के कई हिस्सों में बोर्डिंग स्कूल और अनाथालय आरटीई अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। रिलायंस भी था दिनांक 13.07.2012 के अनुदेशों पर रखा गया। समीक्षा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दिशानिर्देश दिनांक 18.04.2012 के निर्णय की तारीख के बाद

[1] (2012) 6 एससीसी 1

जारी किए गए थे और आदेश को वापस लेने का कोई आधार नहीं था। नतीजतन, वर्तमान अपील दायर की गई है।

(5) घटनाओं के अनुक्रम के संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य यह है कि *अंकित (नाबालिग) मामले (सुप्रा)* में निर्णय 02.11.2011 को पारित किया गया था और वर्तमान मामले में स्कैट को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 16.03.2012 को सुरक्षित रखा गया था। आक्षेपित निर्णय दिनांक 18042012 को पारित किया गया था और पुनरीक्षा आवेदन दिनांक 31082012 को खारिज कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय से छह दिन पहले दिनांक 12042012 का है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राजस्थान के अनएडेड प्राइवेट स्कूल सोसायटी मामले (सुप्रा)* में आरटीई अधिनियम को चुनौती देते हुए आरटीई अधिनियम के प्रावधानों की बारीकी से जांच की और सभी पड़ोस में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों सहित पड़ोस के स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के कर्तव्य को भी ध्यान में रखा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत राज्य की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है, जिसे कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा गया था। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता को बोर्डरों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, निदेश जारी किए गए थे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत उपर्युक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उक्त टिप्पणियां निम्नानुसार पढ़ी गई हैं: -

(6) *"13. तथापि, हम चाहते हैं कि सरकार एक पहलू पर स्थिति स्पष्ट करे। 7' यहाँ भारत के कई हिस्सों में बोर्डिंग स्कूल और अनाथालय हैं। उन संस्थानों में दिवा विद्वान और जमाखोर हैं। 2009 का अधिनियम केवल दिन के विद्वानों पर लागू हो सकता है। यह*

बोर्डर्स के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। मामले को संदेह से परे रखने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि 2009 अधिनियम की धारा 35 के तहत जारी किए गए उचित दिशानिर्देश स्पष्ट करें (वह उपरोक्त स्थिति।" राजस्थान केस के अनएडेड प्राइवेट स्कूलों के लिए सोसायटी (सुप्रा) में 12.04.2012 को जारी उक्त निर्देशों के अनुसरण में, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल I शिक्षा और साक्षरता का विकास) ने दिशानिर्देश जारी किए कि धारा 12 की उपधारा 1 के खंड (सी) की प्रयोज्यता दिवा के विद्वानों तक सीमित होगी क्योंकि केवल दिन के विद्वानों के संबंध में पड़ोस मानदंड लागू हो सकते हैं। तदनुसार, अनुदेशों के अनुसार, उक्त अधिनियम के प्रावधान उन आवासीय स्कूलों पर लागू नहीं होंगे जो कक्षा-I से उच्चतर कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश देना शुरू करते हैं। उक्त पत्र की सामग्री निम्नानुसार है

> *"विषय: आवासीय विद्यालयों के संबंध में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 35 (1) के तहत दिशानिर्देश।*
>
> *माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के अनएडेड प्राइवेट स्कूलों की सोसायटी बनाम भारत संघ और एएनएन के मामले में रिट याचिका 95/2010 में दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के निर्णय के पैरा 13 में और इसी प्रकार की रिट © याचिकाओं के साथ टैग की गई और निदेश दिया कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (घ) बोडग और आवासीय विद्यालयों में इसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करते हुए 2009 के लिए अधिसूचना जारी की जाए।*
>
> *2. उपरोक्त मुद्दा निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा (1) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है। उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि स्कूल के विनिदष्ट पड़ोस में रहने वाले कमजोर वर्ग*

और लाभवंचित समूह से संबंधित बच्चों को उक्त खंड में दर्शाई गई सीमा तक उसमें भर्ती किए जाने का अधिकार है और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है, आवासीय स्कूलों का सम्मान करते हुए, हालांकि, (वह धारा12 की उपधारा(1) के खंड(सी) की प्रयोज्यता डीएवी विद्वानों तक सीमित होगी, क्योंकि केवल दिन के विद्वानों के संबंध में पड़ोस मानदंड लागू हो सकता है।

3. बालकों का वृक्ष और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उपधारा(1) के खंड(ग) के उपबंध उन आवासीय विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जो कक्षा 1 से उच्चतर कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश देना शुरू करते हैं।

4. 'उपरोक्त दिशानिर्देश को आवश्यक अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

(7) इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और बाद में जारी किए गए निर्देशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 25% स्कैट्स को आरक्षण प्रदान करने के लिए आरटीई अधिनियम का प्रावधान बोर्डिंग स्कूलों पर लागू नहीं होगा। अपीलकर्ता के रुख को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि चूंकि सैनिक स्कूल कक्षा 6 वीं में शुरू नहीं हुए थे, इसलिए आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) लागू नहीं थी और उक्त मुद्दा विचाराधीन था। 16.02.2012 को, एक निर्णय लिया गया था कि चूंकि सैनिक स्कूल कक्षा 1 में नहीं बल्कि कक्षा 6 में शुरू होते हैं, इसलिए वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता है, इस तथ्य के बावजूद कि वे धारा 2 (एन) (iii) के साथ पठित धारा 2 (पी) के तहत निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल थे। पत्र की प्रासंगिक सामग्री निम्नानुसार है: -

(a) सैनिक स्कूल आरटीई अधिनियम की धारा 2 (एन) (एचआई) के साथ पठित धारा 2 (पी) के तहत निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के

लिए निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों की जिम्मेदारी की सीमा धारा 12 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार है, अर्थात प्रत्येक वर्ष कक्षा 1 में वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के 25% बच्चों की सीमा तक

(b) हालांकि, चूंकि सैनिक स्कूल कक्षा 1 से वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए धारा 12 (1) (सी) के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं।

(8) *जहां तक बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया का संबंध है, धारा 35(1) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है। "* इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि बोडग स्कूलों/सैनिक स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रचालन के दायरे से बाहर रखा गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में भारत संघ द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय उक्त अनुदेशों को केवल इस आधार पर ध्यान में नहीं रखा कि वे निर्णय पारित होने के बाद बाद जारी किए गए थे और लागू नहीं होते थे। इस प्रकार, समीक्षा को अस्वीकार करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।

(9) अपीलकर्ताओं के वकील का यह कहना कि चूंकि सैनिक स्कूल एक जमाखोरी स्कूल है और बच्चों को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे में प्रवेश पाने के लिए प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है, इसलिए स्वीकृति की आवश्यकता है क्योंकि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य पड़ोस में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बोर्डिंग स्कूलों तक विस्तारित नहीं होगा। पड़ोस की अवधारणा को इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूरे राज्य में हो। प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी -3) के अवलोकन से पता चलता है कि

रिट याचिकाकर्ता और उसकी मां जिला भिवानी से संबंधित हैं, जबकि अपीलकर्ता-स्कूल जिला कमल में स्थित है और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं के पड़ोस में कभी नहीं रहता था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 6 निम्नानुसार है: -

> "**6. विद्यालय स्थापित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य**- इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आस-पड़ोस के ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर, जो विहित किया जाए, एक स्कूल स्थापित करेगा, जहां वह इस प्रकार स्थापित नहीं है।

(10) इसी प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 8(ख) के अंतर्गत समुचित सरकार को पास-पड़ोस में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। आरटीई अधिनियम की धारा 8 (बी) निम्नानुसार पढ़ती है: -

> *"8. समुचित सरकार के कर्तव्य- समुचित सरकार*
>
> *(a) xxx xxx xxx*
>
> *(b) धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट पड़ोस के स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करना; "*

(11) 'सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान केस (सुप्रा) *में माननीय सर्वोच्च न्यायालय* उक्त प्रावधानों की जांच करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पड़ोस के स्कूलों की अवधारणा का अर्थ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित स्कूल होगा ताकि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पूरी की जा सके। 'पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

> "7.......... *धारा 4 में अन्य बातों के साथ-साथ दाखिला न लेने वाले अथवा प्रारंभिक शिक्षा पूरी न करने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का प्रावधान है। धारा 5 उस स्थिति से संबंधित है जहां प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का कोई*

प्रावधान नहीं है, तो, ऐसी स्थिति में, एक बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए धारा 2 के खंड (एन) के उपखंड (एचआई) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूल को छोड़कर, किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार होगा। अध्याय III उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता-पिता के कर्तव्यों का प्रावधान करता है। धारा 6 उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर ऐसे क्षेत्रों या पड़ोस की सीमाओं के भीतर एक स्कूल स्थापित करने का दायित्व लगाती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जहां यह स्थापित नहीं है, 2009 अधिनियम के लागू होने से 3 साल के भीतर। ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों को नेबरहुड स्कूल सुविधा प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। "

(12) अपीलकर्ता के वकील ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 के नियम 6 पर भरोसा किया (संक्षेप में 'आरटीई नियम') - धारा 5 का संदर्भ यह दलील देने के लिए भी किया गया था कि बच्चे को धारा 2 के खंड (एन) के उप-खंड (iii) और (iv) में स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसमें एक सैनिक स्कूल शामिल था क्योंकि संदर्भ एक निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल के लिए था। तदनुसार, यह तर्क दिया गया था कि 25% के तहत आरक्षण की धारा 12 (1) (सी) के तहत लाभ बोर्डिंग स्कूलों में नहीं हो सकता है। आरटीई नियमों के नियम 6 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है: -

"6. पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएंः- (1) 'पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्कूल की स्थापना की जानी है, निम्नलिखित होंगे-

(a) कक्षा I से V तक के बच्चों के संबंध में, पड़ोस के एक किमी की पैदल दूरी के भीतर एक स्कूल स्थापित किया जाएगा

(b) छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों के संबंध में, पड़ोस के तीन किमी की पैदल दूरी के भीतर एक स्कूल स्थापित किया जाएगा।

(2) जहां कहीं अपेक्षित होता है, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी VI से VIII तक की कक्षाओं को शामिल करने के लिए I से V तक की कक्षाओं वाले मौजूदा स्कूलों का उन्नयन करेगा और कक्षा VI से शुरू होने वाले स्कूलों के संबंध में, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण, जहां कहीं अपेक्षित हो, I से V तक कक्षाएं जोड़ने का प्रयास करेगा।

(3) कठिन भू-भाग, भूस्खलन, बाढ़, सड़कों की कमी और सामान्य रूप से छोटे बच्चों के लिए उनके घरों से स्कूल तक पहुंचने वाले खतरे के जोखिम वाले स्थानों में, उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचने के लिए स्कूल का पता लगाएंगे।

(4) उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अभिज्ञात छोटी बस्तियों के बच्चों के लिए, जहां उपनियम (1) के अंतर्गत विनिदष्ट पड़ोस के क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी उक्त नियम में विनिदष्ट क्षेत्र अथवा सीमाओं में छूट देते हुए स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसी पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

(5) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों में, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण ऐसे स्थानों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक पड़ोस में स्कूल स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

(6) स्थानीय प्राधिकरण पड़ोसी स्कूलों की पहचान करेगा जहां बच्चों को भर्ती किया जा सकता है और प्रत्येक बस्ती के लिए ऐसी जानकारी सार्वजनिक करेगा. ;

(7) विकलांग बच्चों के संबंध में, जो उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं, उपयुक्त सरकार या

स्थानीय प्राधिकरण उन्हें स्कूल जाने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए उचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे।

(8) उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल में बच्चों की पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण बाधित न हो।"

(13) धारा 5, 6, 8 और नियम 6 और सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के मामले (सुप्रा) *के फैसले में प्रतिपादित सिद्धांतों को एक संयुक्त पढ़ने* से पता चलता है कि आरक्षण का उद्देश्य पड़ोस के क्षेत्र से संबंधित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और इसे पूरे राज्य में नहीं बढ़ाया जा सकता है। और 25% आरक्षण की अनिवार्य आवश्यकता बोर्डिंग स्कूलों और अनाथालयों तक विस्तारित नहीं होगी जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है।

(14) उत्तरदाताओं के वकील ने उपर्युक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष पर भरोसा किया है कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों और विशिष्ट श्रेणी के स्कूलों सहित सभी स्कूल आरटीई अधिनियम के दायरे में आते हैं और इसलिए, अपीलकर्ता आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था। तर्क दिया कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान था और हरियाणा राज्य के निवासी स्कूलों में प्रवेश के हकदार थे। हालांकि, *सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के मामले (सुप्रा) में* फैसले के पैरा नंबर 13 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर , जिसमें स्पष्ट रूप से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि आरटीई अधिनियम के प्रावधान बोर्डिंग स्कूलों पर लागू नहीं होंगे, रिट याचिकाकर्ता के पास कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं हो सकता है।

(15) नतीजतन, विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 18.04.2012 के निर्णय और

दिनांक 31.10.2012 के समीक्षा आवेदन को खारिज करने के आदेश को अनिवार्य रूप से रद्द कर दिया जाए और रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाए और उसे दी गई स्वीकारोक्ति जारी नहीं रह सकती। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता-स्कूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 को सत्र 2012-13 के लिए 6 वीं कक्षा में अध्ययन करने के अपने खाते पर तुरंत एक प्रमाण पत्र देगा ताकि वह कहीं और प्रवेश ले सके।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल , हरियाणा